



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 25 सितम्बर, 1998/3 आश्विन, 1920

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग
विधायी एवं राजभाषा खण्ड

अधिसूचना

शिमला-2, 25 सितम्बर, 1998

संख्या एल० एल० आर० (राजभाषा)बी०(16)-30/98. —“दि लैण्ड एक्वीजिशन (हिमाचल प्रदेश
अमैन्डमेंट) ऐक्ट, 1986 (1986 का 17)” के राजभाषा (हिन्दी) अनुवाद को हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के

तारीख 9 सितम्बर, 1998 के प्राधिकार के अधीन एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है। और यह हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 के अधीन, उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि)।

भूमि अर्जन (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1986

(1986 का 17)

(11 जुलाई, 1986 को राष्ट्रपति द्वारा यथा अनुमत)

हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के संतीयें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भूमि अर्जन (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, सं संज्ञा नाम। 1986 है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् धारा 18 का मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 18 की उप-धारा (2) के विद्यमान धारा 18 का संशोधन। परन्तु के अन्त में आए "।" चिह्न के स्थान पर ":" चिह्न रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वितीय परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह और कि कलक्टर, यदि उसका समाधान हो जाता है कि आवेदक समय पर आवेदन करने से पर्याप्त हेतुक से निर्वाचित किया गया या इस धारा के अधीन, छः सप्ताह की अवधि के अवसान के पश्चात् किन्तु छः मास की अवधि के भीतर आवेदन ग्रहण कर सकेगा।"

3. मूल अधिनियम की धारा 31 में,—

धारा 31 का संशोधन।

(क) उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा (3-क) अन्तः-स्थापित की जाएगी :—

"(3-क) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, यदि भूमि में हितवद्ध व्यक्ति, धन के बजाय, वस्तु के रूप में प्रतिकर स्वीकार करने के लिए राजमंद है तो, कलक्टर, प्रागे समुचित सरकार की मजूरी से, किसी भूमि के बारे में धन के रूप में प्रतिकर अधिनिर्णीत करने के बजाय, अर्जित भूमि के आदान-प्रदान में समतुल्य मूल्य की कोई अन्य भूमि देगा और तद्वारा आदान-प्रदान में इस प्रकार दी गई भूमि के बाजार मूल्य के अनुसार सम्पूर्णतः या भागतः अधिनिर्णीत प्रतिकर संदत्त करेगा।"; और

(ख) उप-धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(4) उप-धारा (3) और उप-धारा (3-क) की किसी बात का, यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह भूमि में हितवद्ध और उसके संबंध में संविदा करने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति के साथ कोई ठहराव

करने की कलक्टर की शक्ति में कोई हस्तक्षेप करती है या उसे परिसीमित करती है।”

नई धारा 52-क का अन्तःस्थापन। 4. मूल अधिनियम की धारा 52 के पश्चात्, निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“52-क. प्रतिकर का संरक्षण.—इस धारा के अधीन अधिनिर्णीत या अधिनिर्णीय कोई प्रतिकर —

(क) उसे प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति को वास्तविक रूप से यह संदत्त किया जाता है, से पूर्व; या

(ख) ऐसी किसी भूमि जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश के निष्पादन में कुर्की या विक्रय के लिए दायी नहीं है, के बारे में उसे प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति को यह वास्तविक रूप से संदत्त किया जाने से पूर्व या पश्चात्; लेनदार की प्रेरणा पर, प्रतिकर के हकदार किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी मांग के लिए किसी न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा या किसी न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश की तुष्टि में अभिग्रहण, कुर्की या परिवर्द्धकरण का दायी नहीं होगा, और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, न तो शासकीय समनुदेशित न ही किसी विधि के अधीन नियुक्त कोई रिसीवर किसी ऐसे प्रतिकर के विरुद्ध कार्यवाही करने या किसी दावे का हकदार होगा।”

निरसन और व्यावृत्तियां। 5. भूमि अर्जन (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1979 (1980 का 4) एनद्द्वारा निरसित किया जाता है:

परन्तु इस धारा के अधीन इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन की गई सभी नियुक्तियां, बनाए गए नियम और आदेश, जारी की गई सभी अधिसूचनाएं और नोटिस, किए गए सभी संव्यवहार तथा संस्थित सभी वाद और कार्यवाहियां, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत हैं, इस अधिनियम के अधीन क्रमशः की गई, जारी की गई, बनाए गए, जारी की गई, किए गए और संस्थित की गई, समझी जाएंगी।